

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून-दिनांक 3। मार्च, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में राजकीय इंटर कालेज, मानले जनपद पिथौरागढ़ के अनावासीय भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-5 ख 1/63261/जीण-शीर्ण/2007-08, दिनांक 01 मार्च, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इंटर कालेज, मानले जनपद पिथौरागढ़ के अनावासीय भवन निर्माण कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रु0 89.00 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रु0 2.00 लाख (रु0 दो लाख मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्या-1010/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनांक 03 अगस्त, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1974/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनांक 26 दिसम्बर 2007 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी नयी धनराशि रु0 1900.00 लाख में से नियमानुसार लगाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- 1- कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- 2- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 3- कार्य पर उताना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।
- 4- एक मुस्त प्राविधानों के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- 5- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पन्न करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जाय।
- 7- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 8- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कार्य कराने समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाय।



9- निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाय, किसी भी दशा में आगणन को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित ग्राहक पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याक्षा में अनुमोदित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिचय-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-आयोजनागत-00-11-राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण शीर्ण भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-694(P)/XXVII(3)/2008, दिनांक 25 मार्च 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्या-456(1)/XXIV-3/08/02(123)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 6- अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 7- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 8- कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 9- जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
- 10- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
- 12- सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।
- 13- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
- 14- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(15)

(पी0एल0शाह)

उप सचिव